कापियां लेने पर पिछले कई वर्षों से विवश करता आ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तेल निगम के किस नियम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से इस प्रकार की फोटो कापियां लेना अपेक्षित है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस वितरक के विरुद्ध की गयी अनेक शिकायतें निचले स्तर पर दबायी जा रही हैं ;

(घ) क्या सरकार इन शिकायतों के बारे में कोई जांच कराने का प्रस्ताव रखती हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) जी, हां। मैसर्स जी०एस० एन्टरप्राइज अपने उपभोक्ताओं को निवास स्थान को प्रमाणित करने के लिए राशन कार्ड, किराया रसीद, बिजली का बिल अथवा एल आई जी की रसीद के रूप में कागजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है कि प्रत्याशित उपभोक्ता अपने निवास सम्बन्धी कोई प्रमाण पेश करें। तथापि, अपनी पहचान और निवास स्थान को सत्यापित करने और अनधिकृत गैस कनेक्शन के रिलीज होने से बचने के लिए यह वितरक निवास स्थान के लिए कागजी साक्ष्य की मांग कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरकों के लिये निर्धारित कोटा

121. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रत्येक वितरक के लिये 6,500 रिफिल प्रति मास का कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने गैस-वितरक हैं जिन्हें उपर्युक्त कोटे से कम गैस की सप्लाई प्राप्त होती है ;

(ग) क्या सरकार उन गैस-वितरकों को जिन्हें 6,500 रिफिलों का निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता, गैस की सप्लाई में इस कमी को पूरा करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) एल० पी० जी० वितरकों के लिए कोई भी कोटा निर्धारित नहीं किया गया है फिर भी तेल कम्पनियों ने एल०पी०जी० वितरकों द्वारा बेचे जाने वाले रिफिलों की अधिकतम सीमा निर्धारित की हैं। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत एल०पी०जी० वितरकों के लिए अधिकतम सीमा 6500 रिफिल प्रतिमाह निर्धारित की गई हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) बाटलिंग क्षमता सहित उत्पाद की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं होने पर नए उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत तेल कम्पनियां हैए कनेक्शन जारी करती है। नई वितरण शिपों द्वारा भी कनेक्शन दिए जाते हैं ताकि चरणबद्ध रूप से उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्तर तक लाया जा सके।

LPG Production at Cochin Refinery

122. SHRI THOMAS KUTHIRAVATTOM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the quantity of LPG produced at Cochin Refinery annually;

(b) how much of it is reserved for use in Kerala;

(c) whether it is a fact that 90 per cent of the gas produced in Kerala is exported outside the State thereby exposing Kerala consumers to long waiting lists; and

(d) whether any ban has been imposed on giving new connections in Kerala State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) and (b) The amount of LPG produced by Cochin Refinery during 1986-87 was 123720 MT. The demand for packed LPG in Kerala is about 37000 MT per annum;

(c) No, Sir;

(d) While Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and Bharat Petroleum Corporation Ltd. are continuing to release new cooking gas connections in Kerala, Indian Oil Corporation Ltd. has temporarily suspended release of new connections all over the country including Kerala due to heavy backlog, reduced bulk availability and operational constraints.

Clearance to Thermal Power Station in Rayalaseema Region

123. SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Andhra Pradesh State Electricity Board had submitted a feasibility report for installation of a 2x210 MW Thermal Power Station in the Rayalseema region to the Central Electricity Authority for Techno-economic clearance; and

(b) if so, what is the decision taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI MATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) The proposal in respect of installation of a 2x210 MW thermal power station in Rayalaseema (Muddanur) has been techno-economically cleared by the Central Electricity Authority, subject to confirmation of coal linkage, clearance being obtained by the State Electricity Board from environmental angle and compliance of conditions stipulated by the State Pollution Control Board.

Prices of Aminophylline/Theophylline

124. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what prices were fixed for Aminophylline and Theophylline under the Drugs Price Control Order 1979;

(b) whether BICP had recommended the prices of these drugs;

(c) if so, when and what price was recommended for each drug; and

(d) what is the present prevailing price of each drug?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) and (d) No Prices were fixed for Aminophylline and Theophylline under the Drugs (Prices Control) Order, 1979.

(b) and (c) Since the DPCO, 1979 has been repealed, the question of notifying prices under this order does not arise.

Sales turn-over of each brand of Methdilazine HCL

125. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Mathdilazine HCL has been recommended for price decontrol by Kelkar Committee;

(b) if so, what are the names of brands being marketed in the country based on this drug along with the names of producers;